695 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोपित भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने सात दिन की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय के हवाले कर दिया। उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था।

पेंशन की टेंशन न लें पूर्व सैनिक : राजनाथ

आश्वासन ▸ बोले–पेंशन विसंगति दूर करने और उसे जारी करने में अब देरी नहीं होगी

रक्षा मंत्री ने कहा, अब कॉल सेंटर पर दूर होने लगी पूर्व सैनिकों की समस्याएं

जागरण संवाददाता, लखनऊ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अपने जवानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। पूर्व सैनिकों को पेंशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको पेंशन समय से मिले, इसके लिए कुछ और बदलाव जल्द होंगे। देश में जितना सम्मान सेवारत जवानों का है, उतना ही सम्मान पूर्व सैनिकों का भी है। आज भी हमारे पूर्व सैनिकों में कुछ कर गुजरने की हसरत है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित एएमसी स्टेडियम में आयोजित 172वीं रक्षा पेंशन अदालत में रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना के जवानों के कारण देश ऊंचाइयों को छू रहा है। राजनाथ सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने रक्षा पेंशन अदालत में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पेंशन विसंगति दूर करने और उसे जारी करने में अब देरी नहीं होगी। पेंशनरों को अब अपनी पेंशन की दिक्कत के लिए भटकने की जरूरत नहीं है।

लखनऊ कैंट स्थित एएमसी स्टेडियम में शनिवार को दो दिवसीय रक्षा पेंशन अदालत के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जागरण

रक्षा लेखा विभाग ने उनके लिए एक कॉल सेंटर बनाया है।

पेंशनरों का डाटा होगा डिजिटल : रक्षा पेंशन अदालत के दौरान रक्षा लेखा महानियंत्रक संजीव मित्तल ने कहा कि जल्द ही रक्षा लेखा मुख्यालय सेंट्रल कंप्रेसिव पेंशन सिस्टम लागू करेगा। इसके तहत डिजिटल माध्यम से सारा डाटा रक्षा लेखा के सिस्टम में फीड होगा। यहां डाटा की प्रोसेसिंग के बाद सही पेंशन का निर्धारण कर उसे जारी किया जाएगा। इस सिस्टम में मानवीय चूक नहीं होगी, जिससे पेंशनरों को उनकी पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

पेंशन निर्धारण का 60 फीसद काम पूरा : संजीव मित्तल ने कहा कि जालंधर में 1987 में पहली बार रक्षा पेंशन अदालत लगी थी। रक्षा पेंशन अदालत इलाहाबाद ने एक वेबसाइट तैयार की है जिस पर पेंशन से जुड़े सभी ऑर्डर अपलोड होते हैं। देश में 32 लाख रक्षा पेंशनर हैं। हर साल 80 से 85 हजार नए पेंशनर जुड़ जाते हैं।

ये जानना हमारा हक है कि कौन विदेशी कौन स्वदेशी

राजनाथ सिंह ने कहा कि असम की एनआरसी के दौरान कुछ खामियां रहीं, जिनको दूर किया जा रहा है। सरकार अब पूरे देश में एनआरसी करवाएगी। ये हमारा हक है कि हम जानें कि भारत में कौन स्वदेशी है और कौन विदेशी। फिक्की फ्लो फेस टू फेस कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने असम से आई महिला उद्यमी श्रुतिमाला के सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री था तब भी एनआरसी हुई थी, जिसमें कुछ कमियां रह गई थीं। सरकार पूरे देश में एनआरसी करवा रही है। इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी।

अवमानना मामले में राहुल और येचुरी को मुंबई की अदालत से नहीं मिली राहत

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को अवमानना के एक मामले में राहत देने से इन्कार कर दिया। दोनों नेताओं ने अपने खिलाफ अवमानना की शिकायत रद कराने की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की थी। दोनों नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता ने यह शिकायत दर्ज कराई है। कोर्ट द्वारा अर्जी ठुकराए जाने के बाद अब दोनों नेताओं को इस मामले में सुनवाई का समाना करना होगा। अदालत छह जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी।

दोनों नेताओं ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से आरएसएस को जोड़ने वाला बयान दिया था। उनके उसी बयान के आधार पर आरएसएस कार्यकर्ता धृतिमान जोशी ने राहुल और येचुरी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।

राहुल ने कहा है कि उनके साथ येचुरी के खिलाफ मामले को जोड़ा जाना गलत है। वकील कुशल मोर के माध्यम से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि कोर्ट ने कांग्रेस नेता और येचुरी की अर्जी संयुक्त रूप से रिकार्ड किया है। हालांकि इस तरह की संयुक्त सुनवाई केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के तहत ही की जा सकती है। मौजूदा मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होता है।

अर्जी में कहा गया है कि येचुरी और वह दो पार्टियों से संबंध रखते हैं जो काफी भिन्न हैं और विपरीत विचारधारा वाली हैं। कथित बयान राजनीतिक है और संयुक्त सुनवाई होने से राहुल के बचाव को नुकसान पहुंच सकता है।

सितंबर 2017 में पत्रकार लंकेश की बेंगलुरु में उनके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में कथित रूप से कट्टरपंथी दक्षिणपंथी समूह का हाथ बताया गया था। जोशी ने आरोप लगाया है कि राहुल ने संवाददाताओं से कहा था कि जो भी भाजपा की, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है उसपर दबाव डाला जाता है, उसकी पिटाई होती है और यहां तक कि हत्या कर दी जाती है। येचुरी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस के लोगों ने लंकेश की हत्या की।

कांग्रेस नेता के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग खारिज

जासं, नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के लिए दायर याचिका को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया।

अधिवक्ता जोगिंदर तुली ने याचिका में कहा था कि राहुल गांधी ने 2016 में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तुली ने पहले पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन उसने केस दर्ज नहीं किया। तब वह कोर्ट चले गए। अदालत के जवाब मांगने पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। याचिकाकर्ता चाहे तो अदालत में केस दायर कर सकते हैं, लेकिन इस शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस की इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने शिकायत खारिज कर दी।

उपराज्यपाल लोगों की जरूरतों पर ध्यान दें वंचित वर्ग के उत्थान के लिए काम करें : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों और उपराज्यपालों से लोगों की जरूरतों पर ध्यान देने और अल्पसंख्यकों समेत समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करने की अपील की है। प्रधानमंत्री शनिवार को यहां राज्यपालों और उप राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों का भी विशेष उल्लेख किया, जहां रोजगार पैदा करने और गरीबों और दलितों की बेहतरी के लिए मौजूद नए अवसरों के उपयोग करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यपालों और उप राज्यपालों को अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए लोगों की जरूरतों पर भी ध्यान देना चाहिए। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ काम करते और उनका उपयोग करते हुए उन्हें अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और युवाओं समेत समाज के वंचित वर्गों की भलाई और उत्थान के लिए काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघीय ढांचे को साकार करने के लिए राज्यपाल को बहुत अहम भूमिका निभानी होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2022 में अपनी आजादी की 75वीं और 2047 में 100वीं जयंती मनाने जा रहा है। ऐसे में सरकारी मशीनरी को लोगों के करीब तक ले जाने और उन्हें सही रास्ता दिखाने में राज्यपालों की भूमिका और अहम हो जाती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को 2025 तक टीबी जैसी बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है और इस काम में राजभवन का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के चांसलर होने के नेता राज्यपाल छात्रों के माध्यम से ऐसी बीमारियों के प्रति जागरूकता का प्रसार कर सकते हैं।

राज्यपालों के इस 50वें वार्षिक सम्मेलन में 17 लोग ऐसे थे, जो पहली बार राज्यपाल बने थे। जबकि, नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उप राज्यपाल भी मौजूद थे। सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इत्यादि भी शामिल हुए।

नई दिल्ली में शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित सभी राज्यों के राज्यपालों और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को नौकरी में मिलेगा पांच प्रतिशत आरक्षण

नईदुनिया, ग्वालियर: मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरी में पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ग्वालियर में प्रांतीय ओलंपिक खेलों के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि नौकरी में आरक्षण की नीति पर कमलनाथ सरकार काम कर रही है।

मंत्री ने कहा कि 15 साल तक जिन खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में लगातार पदक हासिल करने के बाद भी नौकरी से वंचित रहना पड़ता है, उन्हें शासकीय नौकरी में पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप नई खेल नीति में इसकी व्यवस्था की जा रही है। अंडर 16 प्रांतीय ओलंपिक में सभी सीबीएसई, सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों के बच्चे शामिल होंगे। अभी यह स्पर्धा केवल 16 वर्ष से अधिक आयु समूह के बच्चों में से प्रतिभा चयन के लिए आयोजित की जा रही है।

उधर, शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में आयोजित युवा संवाद एवं प्रतिभाशाली छात्राओं के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण भी देगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर हाल में लोगों को नौकरी में ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना चाहती है।

रामलला को सौंपी गई सुप्रीम फैसले की प्रति

जागरण संवाददाता, अयोध्या

न्याय की अवधारणा के अनुरूप फैसले की प्रति संबंधित पक्षकारों को सौंपी जानी चाहिए और इस प्रति पर उस पक्ष का विशेष अधिकार बनता है, जिसके हक में फैसला आया हो। इसी क्रम में रामलला की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं का दल शनिवार को दिल्ली से रामलला के दरबार तक आ पहुंचा। अयोध्या आने वाले अधिवक्ताओं के दल की अगुवाई कर रहे दिग्गज अधिवक्ता के. परासरन ने फैसले की प्रति रामलला को अर्पित की। अधिगृहीत परिसर में ही स्थित रामचरित मानस भवन के अतिथि गृह में रामलला की ओर से रामलला के पदेन रिसीवर मंडलायुक्त मनोज मिश्र ने यह प्रति स्वीकार की। उन्हें यह प्रति विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय, अंतरराष्ट्रीय संरक्षक दिनेशचंद्र एवं रामलला के सखा त्रिलोकीनाथ पांडेय ने परासरन की ओर से दी। 929 पेज का फैसला और रामजन्मभूमि की प्रामाणिकता प्रशस्त करते साक्ष्यों से युक्त 116 पेज का विशेष परिशिष्ट अधिवक्ताओं की उस मेहनत का परिणाम है, जिसे उन्होंने स्थानीय सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर किया।

अयोध्या आने वाले अधिवक्ताओं के दल में के. परासरन सहित उनके अधिवक्ता पुत्र मोहन एवं सतीश परासरन, वैद्यनाथन व उनके पुत्र हरीश वैद्यनाथन, पीवी योगेश्वरन, स्वरूपमा चतुर्वेदी, विक्रम बनर्जी, श्रीधरन, डी. भरत कुमार, भक्तिवर्धन आदि रहे। अधिवक्ताओं ने रामलला का दर्शन भी किया। इससे पूर्व उन्होंने पुण्यसलिला सरयू में डुबकी लगाई और तीसरे पहर विहिप, संतों तथा रामनगरी की ओर से सम्मान स्वीकार किया। विहिप के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक दिनेशचंद ने अधिवक्ताओं को सम्मान स्वरूप उत्तरीय, मिष्ठान के साथ रामजन्मभूमि न्यास की ओर से प्रस्तावित रामलला मंदिर के मॉडल का छाया चित्र प्रदान किया।

इस मौके पर रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास, आचार्य पीठ दशरथमहल के महंत बिंदुगाद्याचार्य देवेंद्रप्रसादाचार्य, रामलला के सखा त्रिलोकीनाथ पांडेय, साध्वी ऋतंभरा, पूर्व सांसद विनय कटियार आदि की नुमाइंदगी रही।

अयोध्या के कारसेवकपुरम में रामलला की पैरवी करने वाले अधिवक्ता केशव पारासरन को सम्मानित करते विहिप के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक दिनेशचंद्र। जागरण

अयोध्या फैसले पर 15 दिसंबर तक रहें सतर्क : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में रही शांति व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की सराहना की है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि इस मामले में अभी पंद्रह दिसंबर तक समुचित और सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध रखे जाएं। कानून व्यवस्था और अन्य विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग की।

22 फीसद भूजल सूख गया या नाजुक स्थिति में है : शेखावत

नई दिल्ली, एएनआइ : देश में भूमिगत जल संपदा की स्थिति चिंताजनक है। भूमिगत जल का करीब 22 फीसद या तो सूख चुका है या फिर घटकर नाजुक स्तर तक पहुंच गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने भूमिगत जलस्तर की मैपिंग पर काम शुरू कर दिया है। इससे उनका बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।

नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान शेखावत ने कहा कि उनकी सरकार अगले दो साल में देश में भूमिगत जलस्तरों का पूरी तरह से मैपिंग कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिन जिलों में दोहन के कारण भूमिगत जल नाजुक स्तर तक पहुंच चुका है वहां मार्च 2020 तक मैपिंग का काम पूरा हो जाएगा।

शेखावत ने कहा, 'भारत में कुल भूमिगत जल संसाधन में से करीब 22 फीसद या तो सूख गए हैं या फिर सूखने के कगार पर हैं। इनका नाजुक तरीके से दोहन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेरी सरकार ने भूमिगत जलस्तर की मैपिंग कराने का काम शुरू किया है। हमने करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर में काम पूरा करा लिया है।

बोबडे ने गजराज से लिया आशीर्वाद...

देश के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की। परिसर में उन्होंने भगवान गजानन (गणेश) का स्वरूप माने जाने वाले गज (हाथी) का भी आशीर्वाद लिया। बोबडे इस दौरान पारंपरिक पहनावे में थे। प्रेट्र

छत्तीसगढ़ में अब साक्षर भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इससे राज्य में अब कोई भी साक्षर पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। अभी तक पंच पद के लिए पांचवीं और पंच के ऊपर के पदधारी के लिए आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य था।

मुख्यमंत्री निवास पर शनिवार को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्री परिषद के बैठक में अनुमोदित किया गया। यह प्रस्ताव अब विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में निःशक्त व्यक्ति के निर्वाचित नहीं होने की स्थिति में संबंधित पंचायतों में उनके नामांकन का प्रावधान नहीं है। इन प्रावधानों को संशोधन किए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अब जिन पंचायतों में निर्वाचन के बाद निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में वहां निःशक्त व्यक्ति को नामांकित किया जाएगा।

चिटफंड कंपनियों पर सख्ती के मूड में सरकार : छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों पर सरकार सख्ती के मूड में आ नजर आ रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामने पुलिस अधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिया। इसमें बताया गया कि निवेशकों को धन वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिलासपुर में दर्ज एक मामले में कुर्की के जरिये निवेशक को 2.80 लाख रुपये की राशि वापस कर दी गई है। राज्य में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 403 मामले दर्ज हैं। इनमें 154 की कुर्की कर दी गई है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- दो नए विवि खुलेंगे, जिसमें एक उद्यानिकी विवि महात्मा गांधी के नाम होगा
- राज्य के तीनों आदिवासी विकास प्राधिकारणों के अध्यक्ष पद को लाभ के पद के दायरे से किया गया बाहर
- ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी सहमति से जमीन अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा और परिसंपत्ति के लिए दोगुना मुआवजा

उत्तर प्रदेश में उल्टा पड़ा कांग्रेस का दांव, बढ़ा असंतुष्टों का कुनबा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : संगठन में सुधार की उम्मीद रख रही कांग्रेस के दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं। पहले तो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने वरिष्ठ कांग्रेसियों से अधिक युवाओं को तरजीह देकर उन्हें नाराज कर दिया। फिर उन्होंने शिकवा किया तो पार्टी ने नोटिस थमा दिए। इसे 'इलाज' मानकर चल रही कांग्रेस बदले में एक और सिरदर्द ले बैठी। असंतुष्ट वरिष्ठ कांग्रेसियों का कुनबा बढ़ रहा है।

कांग्रेस के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पुराने कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों दो बैठकें कर अपनी उपेक्षा का दर्द बयां किया। उन्होंने प्रियंका के फैसलों पर असहमति जताते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर पार्टी के हित में सुझाव देने का निर्णय लिया था। इससे नाराज प्रियंका के निर्देश पर अनुशासन समिति ने 11 वरिष्ठ कांग्रेसियों को गुरुवार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांग लिया। इन्हीं में शामिल एक पूर्व विधायक ने बताया कि पार्टी द्वारा हमें नोटिस दिए जाने के बाद दस पूर्व विधायक और हमारे साथ आ गए हैं। अब नोटिस के बाद के कदम पर निर्णय लेने के लिए उन सभी के साथ मिलकर रविवार को पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी के घर पर एक बैठक बुलाई गई है।

गौरवपूर्ण अतीत बताने को इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी

बोले सुबय्या

इतिहास व शिक्षा में वामपंथी इतिहासकारों ने घोला विष, अभाविप का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू, विश्वगुरु बनने में सहायक बनेगा परिषद

जागरण संवाददाता, आगरा

देश की विरासत कभी भी बांटने और बर्बरता की नहीं रही है। यहां राम वनवास गए, भरत ने चरण पादुका की पूजा की, श्रवण ने माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई, मगर भारत के इतिहास और शिक्षा में वामपंथी इतिहासकारों ने विष घोल दिया। गलत इतिहास पेश किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस सुबय्या ने कहा कि देश के इतिहास से वामपंथी जहर खत्म करेंगे, देश का इतिहास पुनः लिखा जाना चाहिए, ताकि देश के गौरवपूर्ण अतीत से जनता को परिचित कराया जा सके।

आगरा कॉलेज मैदान पर बसाए गए गुरु नानकदेव नगर में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन हुआ। सुबय्या ने कहा कि राष्ट्र का सही पुनर्निर्माण तभी माना जाएगा जब आयात-निर्यात में डॉलर की जगह रुपया चलेगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद का भारत स्थायी सदस्य होगा, भारत की अधिकृत मातृभाषा हिंदी होगी। गरीबी दूर होगी, महिलाएं सुरक्षित होंगी। यह जब तक नहीं होता तब तक अभाविप संघर्ष करेगा।

मुख्य अतिथि पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एन. नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि भारत विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, इसमें अभाविप की भी सहभागिता होनी चाहिए। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में गणित से लेकर विज्ञान में दुनियाभर में भारतीयों का डंका बजा है, अब समय आ गया है जब भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी दुनिया का प्रतिनिधित्व करे। नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि राम मंदिर के लिए अभाविप ने संघर्ष किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभाविप ने सुझाव दिए।

उद्घाटन समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल भी उपस्थित रहे।

आगरा में अभाविप के 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, आंबेडकर विवि के कुलपति डॉ. अरविंद दीक्षित और अन्य। जागरण

तीसरी बार अध्यक्ष बने सुबय्या, राष्ट्रीय महामंत्री बनीं निधि

केंद्रीय चुनाव अधिकारी प्रो. डीके शाही ने डॉ. एस सुबय्या को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। वह लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। वहीं, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री निधि त्रिपाठी को राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत किया गया। निधि जेएनयू की शोध छात्रा हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी